



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 451]
No. 451]नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 1997/कार्तिक 30, 1919
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 1997/KARTIKA 30, 1919

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(चीनी और खाद्य तेल विभाग)

आधिकारिक

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1997

सा.का.नि. 656 (अ)—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) को धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 1997 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 में—
(1) अध्याय 6 के नियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—
“गने के विकास के लिए निवेशों को व्यवस्था करने के लिए ऋण 17क (1) केन्द्रीय सरकार, समिति की सिफारिशों और किन्हों अन्य सुसंगत कारकों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपने क्षेत्र में गने के विकास के संबंध में किसी उपक्रम को निधि से दो बर्बं की अधिक के लिए ऋण का संदाय मंजूर कर सकती है, अर्थात् :—
(क) बीजों के क्रय के लिए,
(ख) उर्वरकों के क्रय के लिए,
(ग) कीटनाशीमारों के क्रय के लिए।
(2) चीनी उपक्रम द्वारा इस नियम के अधीन ऋण के लिए आवेदन समिति को प्ररूप III-क में किया जाएगा।
(3) मंजूरीकृत ऋण, मिल के कमान क्षेत्र में, मिलों द्वारा बनाई गई किसी स्कीम के अधीन गना उत्पादकों को दे दिया जाएगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट और मिलों को यथा लागू ऋण के निबंधन और शर्तें बिना उपांतरण के हिताधिकारी गना कृषकों को लागू होंगे।
(4) इस नियम के अधीन ऋण निम्नलिखित क्रम में होंगे :—
(क) 2500 टन (प्रतिष्ठापित क्षमता) प्रतिदिन पीमने वाले कारखानों के लिए 50.00 लाख रुपए तक,

- (ख) 2501-3500 टन (प्रतिष्ठापित क्षमता) प्रतिदिन पीसने वाले कारखानों के लिए 75.00 लाख रुपए तक,
 (ग) 3501-5000 टन (प्रतिष्ठापित क्षमता) प्रतिदिन पीसने वाले कारखानों के लिए 1.00 करोड़ रुपए तक,
 (घ) 5001 टन से अधिक और 10000 टन (प्रतिष्ठापित क्षमता) तक पीसने वाले कारखानों के लिए 1.50 करोड़ रुपए तक ।

(5) ऋण केवल तभी अनुदत्त किया जाएगा जब चीनी उपक्रम आवेदन किए गए ऋण का न्यूनतम दस प्रतिशत अपने स्रोतों से अतिरिक्त धन के रूप में अभिदाय करें ।

(6) केन्द्रीय सरकार निधि में से उपर्युक्त ऋण का संदाय केवल उन्हीं चीनी मिलों को प्राधिकृत करेगी जिन्होंने उपर्युक्त ऋण के संवितरण के समय निधि के शोध्य हुई सभी राशियों का प्रतिसंदाय कर दिया हो ।

(7) ऋण चीनी उपक्रम को, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिश्चित निबंधनों और शर्तों पर, जिसमें भारतीय चीनी मिल संगम, नेशनल फैडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैब्रीज लिमिटेड, संबंधित चीनी मिल, स्थानीय राज्य सरकार कृत्यकारी के प्रतिनिधियों और गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों की समिति द्वारा ऋण के उपयोग, स्कीम जिसके लिए ऋण अनुदत्त किया गया है कि प्रगति, ऋण के ब्याज सहित प्रतिसंदाय और निधि के खाते में प्रेषण को मोनीटर करने का उपबंध भी सम्मिलित है द्विदस्तीय करार के निष्पादन पर सीधे संवितरित कर दिया जाएगा ।

(8) इस नियम के अधीन अनुदत्त ऋण पर नी प्रतिशत प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की रियायती दर होगी ।

(9) ऋण के प्रतिसंदाय के लिए कोई अधिस्थगन नहीं होगा ।

(10) ब्याज सहित ऋण का प्रतिसंदाय चार अद्वितीय किश्तों में किया जाएगा, अर्थात् संवितरण की तारीख से दो वर्ष की कुल अवधि में ।

(11) उप नियम (7) के अधीन निष्पादित द्विदलीय करार के उपबंधों के अनुसार ऋण या उस पर ब्याज की रकम के प्रति-संदाय में कोई अतिक्रम होने की दशा में, चीनी उपक्रम द्वारा अतिक्रम की रकम पर दाइ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज संदेय होगा ।

(12) मूलधन या उस पर शोध्य ब्याज के प्रतिसंदाय में अतिक्रम की दशा में, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सरकार के पास संबित चीनी मिल के किसी दावे में से उक्त अतिशोध्यों को काट सकेगी ।'

(ii) प्ररूप (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप -III" क

नियम 17-क (2)/

(चीनी विकास निधि से गन्ना विकास के अधीन बीजों,

उर्वरकों और कीटनाशीमारों के लिए ऋण के लिए आवेदन)

1.	मिल का नाम और पता	:
2.	(क) प्रतिष्ठापन की तारीख	:
	(ख) सेक्टर	:
	(ग) पीसने की क्षमता	:
	(i) अनुज्ञापि प्राप्त	:
	(ii) प्रतिष्ठापित	:
2.	पूर्ववर्ती तीन चीनी मौसमों के दौरान उपलब्ध गने और पेराई किए गए गने की मात्रा	:
3.	मदे जिनके लिए ऋण का आवेदन किया गया है (बोर्ड संकल्प, यदि कोई हो संलग्न करें)	:
4.	मदानुसार भौतिक लक्ष्य (निवेशों की मात्रा और उसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र)	:
5.	स्कीम के अधीन प्राकलित व्यय	: 1. 2. 3. 4.
6.	मदानुसार आवेदन किए गए ऋण की रकम	:
7.	क्या गन्ना विकास, आधुनिकीकरण के लिए आवेदन किए गए ऋण का चीनी विकास निधि से पहले उपयोग किया गया है, यदि हाँ, तो मंजूरी ऋण दिए जाने का वर्ष (अौरा दें),	:

8. क्या पूर्ववर्ती चीनी विकास निधि ऋण, ऋण में से कुछ अतिशोध्य बकाया है, यदि हाँ तो कितनी रकम
9. पिछले तीन वर्षों में एकक की वित्तीय प्राप्ति (शुद्ध लाभ/हानि उपदर्शित करें)

(अधिभोगी/उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

[फा.सं. 1-5/97-एस.डी.एफ.]

सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

नोट :—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खण्ड-3 में प्रकाशित निम्नलिखित संशोधनों के साथ पठित चीनी विकास निधि नियम, 1983 :—

सा.का.नि. 817 (अ) दिनांक 20 दिसम्बर, 1984, सा.का.नि. 838 (अ) दिनांक 11 नवम्बर, 1985, सा.का.नि. 551 (अ) दिनांक 6 मई, 1988, सा.का.नि. 235 (अ) दिनांक 24 अप्रैल, 1991, सा.का.नि. 441 (अ) दिनांक 28 अप्रैल, 1992, सा.का.नि. 435 (अ) दिनांक 6 मई, 1994 एवं सा.का.नि. 27 (अ) दिनांक 12 जनवरी, 1996

**MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS
(Department of Sugar and Edible Oils)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 1997

G.S.R. 656.....(E) In exercise of the powers conferred by section 9 of the Sugar

Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely:-

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 1997.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983,
 (i) In Chapter VI, after rule 17, the following rule shall be inserted, namely :—
 “ Loan for providing inputs for Sugarcane Development
 17.A (1). The Central Government may, after taking into consideration the recommendations of the Committee and any other relevant factor, accord sanction to the payment of a loan for a period of two years from the Fund to a Sugar undertaking in connection with the development of sugarcane in its area for the

following purposes, namely :

- (a) Purchase of Seeds ;
 - (b) Purchase of fertilizers ;
 - (c) Purchase of Pesticides.
- (2) The application for loan under this rule shall be submitted by the sugar undertaking in Form III-A to the Committee.
- (3) The sanctioned loan shall be passed on to the sugarcane growers in the command area of the mill under a scheme formulated by the mills. The terms and conditions of the loan, as specified by the Central Government, and applicable to the mills, shall, without modification apply to the beneficiary sugarcane farmers.
- (4) The loan under this rule shall be of the following order:-
- (i) Upto Rs.50.00 lakhs for factories upto 2500 Tonnes Crushed Per Day (Installed Capacity) ;
 - (ii) Upto Rs.75.00 lakhs for factories with capacity between 2501-3500 Tonnes Crushed Per Day (Installed capacity) ;
 - (iii) Upto Rs.1.00 crore for factories with capacity between 3501-5000 Tonnes Crushed Per Day (Installed capacity) ;
 - (iv) Upto Rs.1.50 crores for factories with capacities beyond 5001 Tonnes Crushed Per Day and upto 10,000 Tonnes Crushed Per Day (Installed Capacity).
- (5). The loan shall be granted only if the sugar undertaking contributes a minimum of ten percent of the loan applied for from its own resources as margin money.

(6). The Central Government shall authorise payment of the above loan from the Fund only to those sugar undertakings who have repaid all the sums which have become due to the Fund at the time of disbursement of the above loan.

(7). The loan shall be disbursed directly to the Sugar undertaking after it has executed a Bipartite Agreement on such terms and conditions as the Central Government may decide including provisions for monitoring, by a committee with representatives of Indian Sugar Mills Association, National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd., the concerned sugar mill, local State Government functionary and representatives of the sugarcane growers, of the utilisation of the loan, the progress of the scheme for which the loan is granted, repayment of the loan with interest thereon and remittance to the credit of the Fund.

(8). The loan granted under this rule shall carry a concessional rate of simple interest of nine percent per annum.

(9). There shall be no moratorium for repayment of the loan.

(10) The loan together with interest theron shall be repaid in four half yearly instalments i.e. in a total period of two years from the date of disbursement.

(11) In case of any default in repayment of the amount of the loan or interest thereon in accordance with the provisions of the bipartite agreement executed under sub-rule (7), an additional interest at the rate of two and a half percent per annum on the amount of default shall be payable by the Sugar undertaking.

(12) In case of default in repayment of principal or interest due, the Central Government may deduct the said overdues from any claim of the sugar mill pending with the Central Government."

(ii) After FORM - III and the entries relating thereto, the following FORM shall be inserted, namely :-

"FORM - III A

[Rule 17 - A (2)]

APPLICATION FOR LOAN FOR SEEDS, FERTILIZERS AND PESTICIDES UNDER CANE DEVELOPMENT FROM SUGAR DEVELOPMENT FUND (SDF)

1. Name of the Mill and Address :

 - (a) Date of installation :
 - (b) Sector :
 - (c) Crushing Capacity (TCD)
 - (i) Licensed :
 - (ii) Installed :

2. Quantity of cane availability, crushed during the preceding three sugar seasons.
3. Items for which loan is applied for :
(Please attach Board Resolution, if any).
4. Physical targets, item wise, (quantity of input and area covered) :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
5. Estimated expenditure under scheme :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4

6. Amount of loan applied for, item wise.
7. Whether Cane development/modernisation loan applied/availed of from SDF earlier, if so, the year of sanction/release of loan (Give details)
8. Whether any overdues are outstanding against the previous SDF loan. If yes, what amount.
9. Financial status of unit for last 3 years (please indicate Net profit/Loss)

(Signature of Occupier/
Borrower)

- Note:- The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR. 752 (E) dated 28th September, 1983 and subsequently amended vide GSR. 817 (E), dated 20.12.1984, GSR 838 (E), dated 11.11.1985, GSR. 551 (E), dated 6-5-1988, GSR. 235 (E), dated 24.4.1991, GSR. 441 (E), dated 28.4.1992, GSR. 435(E), dated 6.5.1994, and GSR.27 (E), dated 12.1.1996.

[File No. 1-5/97-SDF]
SURENDRA KUMAR, Jt. Secy.

